Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

अगस्त (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **4**

- मुख्यमंत्री ने हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन किया 4
- दूरसंचार की सुगमता एवं विस्तार दिशा-निर्देश 2023 का अनुमोदन 4
- युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप- 2023 5
- मध्य प्रदेश मंत्री परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 5
- म.प्र. निपुण प्रोफेशन में युवाओं का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू 6
- राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा 7
- प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान तीन चरणों में 8
- एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 'उन्मेष' 9
- आरडीएसएस के तहत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर ज़िले के ईमलीखेड़ा में ऊर्जीकृत 10
- रामपुरा-मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना 11
- प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन और राज्य सरकार के मध्य हुआ एम.ओ.यू. 12
- उज्जैन में बनेगा देश का पहला यूनिटी मॉल 13
- प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग और एनआईडी के बीच हुआ एमओयू 13
- नवगठित मऊगंज ज़िला के ज़िलाधीश (कलेक्टर) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) की हुई पद-स्थापना 14
- बालाघाट को मिला स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 15
- प्रधानमंत्री ने रखी संत रविदास मंदिर की आधारशिला 15
- प्रदेश के शासकीय सेवकों को 35 वर्ष की सेवा पर चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलेगा 17

नोट :

- सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ सर्वाधिक कम करने में नर्मदापुरम् वृत्त प्रथम 17
- प्रदेश में मदरसा से संबंधित 4 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी में अधिसूचित 18
- आरडीएसएस के तहत देश का पहला ग्रिड लोकार्पित 18
- मध्य प्रदेश की 100 साल पुरानी संगीत धरोहर मैहर बैंड होगी पुनरुज्जीवित 19
- 16 सीएम राइज़ स्कूल, 19 कन्या शिक्षा परिसर का 1129 करोड़ की लागत से होगा निर्माण 21
- हरदा बना सबसे कम वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने वाला वृत्त 21
- केंद्रीय गृह मंत्री ने जारी किया मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड 22
- नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आयोजित हुआ फूड फेस्टिवल 23
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन 25
- मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री ने दतिया में नवीन एयरपोर्ट का किया शिलान्यास 25
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 26
- 'मध्य प्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति 2023' की स्वीकृति 27
- 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ' योजना का शुभारंभ 28
- शहडोल में राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में 'मुख्यमंत्री स्कूटी योजना' लॉन्च 31
- इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी देश में प्रथम 32
- श्री महाकाल लोक की तर्ज पर जामसांवली हनुमान मंदिर में होगा 'श्री हनुमान लोक'का निर्माण 33
- मध्य प्रदेश में लगेंगी 1772 सूक्ष्म खाद्य उद्यम इकाइयाँ 34
- मध्य प्रदेश में बनेगा रानी अवंती बाई कल्याण बोर्ड 35
- मुख्यमंत्री ने वित्त सेवा अधिकारी संघ की पुस्तक 'वित्त व्यवस्था' का किया विमोचन 36
- साँची सोलर सिटी कम करेगी लगभग 14000 टन कार्बन उत्सर्जन 36
- प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को बीज संघ की सदस्यता 36
- नवाचारी ई-शासन-प्रशासन व्यवस्थाएँ स्थापित करने में आगे बढ़ा मध्य प्रदेश, 23 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिले 37

नोट :

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री ने हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन किया

चर्चा में क्यों ?

31 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास ज़िले की खातेगांव विधानसभा में 1294 करोड़ से अधिक की हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का नाम बाबा सिद्धनाथ परियोजना करने और हरणगांव को तहसील बनाने की घोषणा भी की।
- हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में नर्मदा नदी से देवास जिले की खातेगांव तहसील के नजदीक ग्राम - कुंडगांवखुर्द से 12.60 क्यूसेक जल उद्वहन कर देवास ज़िले के 72 ग्रामों में पहुँचाया जाएगा और 25 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा।
- इससे हंडिया बैराज परियोजना से खातेगांव तहसील में 35000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
- इसके साथ ही हरणगांव सहित छूटे हुए अन्य ग्रामों का सर्वे कर परियोजना का विस्तार किया जाएगा।

दूरसंचार की सुगमता एवं विस्तार दिशा-निर्देश 2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी राईट ऑफ वे नियम, 2022 तथा भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 के साथ संरेखण करते हुए तैयार की गई 'मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति 2023' एवं 'मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु दिशा-निर्देश 2023' का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उक्त नीति लागू किये जाने से मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसरंचना (4G/5G) का शीघ्रता और सुगमता से विस्तार होगा तथा राज्य शासन की आय में वृद्धि होगी।
- प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं एवं अधोसंरचना के सुनियोजित विकास एवं विस्तार को सुनिश्चित करने के लिये 'मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा, अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वायस एवं डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिये नीति एवं दिशा-निर्देश 2019' वर्तमान में लागू है।
- इस नीति की वैधता अवधि दिसंबर, 2023 तक है। वर्तमान में देश के अंदर 5G दूरसंचार की सुविधाएँ भी रोल-आउट कर दी गई है।
- भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2022 को भारतीय तारमार्ग के अधिकार (ROW) (संशोधन) नियम, 2022 जारी किये गए हैं, जिसमें 5G रोल-आउट से संबंधित दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना एवं बुनियादी ढाँचे को और अधिक मज़बूती प्रदान करने के लिये विशिष्ट प्रावधान किये गए हैं।
- दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2023 को भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 जारी किये गए हैं। इन नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति पर स्थापित मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना स्थल पर कोई व्यक्ति/एजेंसी खुदाई या खनन का कार्य करता है तो सामान्य, पोर्टल के माध्यम से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा। इससे दूरसंचार अवसंरचना को अवांछित क्षति से बचाया जा सकेगा।

युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप- 2023

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने 'युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप-2023' देने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि परंपरागत एवं जन-जातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से प्रदेश के 1 हज़ार युवाओं को 3 महीने की अवधि के लिये 10 हज़ार रुपए की मानद फैलोशिप प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
- इस योजना में युवाओं को गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, चित्र तथा शिल्प आदि में से किसी एक कला का प्रशिक्षण 3 माह में दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश मंत्री परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

प्रमुख बिंदु

- केरियर प्रोन्नयन योजना लागू होने से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में दिनांक 01 जुलाई, 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत हो सकेगा।
- चतुर्थ समयमान वेतनमान के दिशा-निर्देश जारी करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। यह वेतनमान स्वीकृत करने पर शासन पर अनुमानित व्यय भार 250 करोड़ रुपए आएगा।
- मंत्रि-परिषद द्वारा 04 नवीन शासकीय महाविद्यालय, शासकीय विधि महाविद्यालय डिंडोरी, शासकीय महाविद्यालय नारायणगंज मंडला, शासकीय महाविद्यालय खिरकिया हरदा, शासकीय महाविद्यालय खड्डी सीधी की स्थापना को स्वीकृति दी गई।
- मंत्रि-परिषद ने ज़िला नर्मदापुरम में नवीन तहसील शिवपुर एवं सीधी ज़िले में नवीन तहसील मड़वास के सृजन की स्वीकृति दी।

नोट :

- मंत्रि-परिषद द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु 20 प्रतिशत भूखंड का आरक्षण तथा इन उद्यमियों को प्रब्याजी और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने के संबंध में मध्य प्रदेश एमएसएमई के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 (यथा संशोधित अक्तूबर 2022) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 6 नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा मुद्रा योजना की पूर्व से मौजूद इकाइयों के लिये, जिनका 01 सितंबर, 2022 के बाद नवीनीकरण किया जा रहा है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पात्र होने पर लाभान्वित किये जाने के लिये योजना में नवीन उद्यम होने संबंधी प्रावधान से छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।

म.प्र. निपुण प्रोफेशन में युवाओं का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशन प्रोग्राम में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन पूरे देश में चलाया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 2021 में 'मिशन अंकुर' प्रारंभ किया गया है।
- मैदानी स्तर पर 'मिशन अंकुर' के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के सहयोग से मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
- इस कार्यक्रम में प्रत्येक ज़िले में एक-एक युवा को संबंधित ज़िला प्रशासन को मिशन अंकुर के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देने का दायित्व सौंपा गया है।

नोट :

- इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिये हज़ारों की संख्या में युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 52 युवा और उत्साही प्रोफेशनल्स का चयन किया गया है।
- चयनित युवा कार्यक्रम क्रियान्वयन और निगरानी में डेटा-आधारित निर्णय लेने, सिस्टम क्षमताओं को बढ़ाने और धरातल पर काम की निरंतरता में ज़िला प्रशासन को सहायता प्रदान करेंगे। सभी चयनित युवाओं का 10 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण 1 से 10 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है।
- चयनित युवा एक NIPUN प्रोफेशनल के रूप में राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक के लगभग 23 लाख छात्रों को सार्थक शिक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने वर्ष 2022 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। वर्ष 2022 के लिये 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, 10 को विक्रम, एक प्रशिक्षक को विश्वामित्र तथा एक खेल हस्ती को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि एकलव्य पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को एक लाख रुपए और शेष को दो लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है।
- वर्ष 2013 से पारंपरिक खेल मलखंब में उत्कृष्टता के लिये स्व. प्रभाष जोशी पुरस्कार प्रारंभ किया गया, जिसमें विजेताओं को दो लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाता है।
- विदित है कि वर्ष 2011 तक एकलव्य पुरस्कार विजेता को 25 हज़ार रुपए और विक्रम, विश्वामित्र और लाईफ टाईम अवार्ड के विजेताओं को 50 हज़ार रुपए की राशि दी जाती थी। वर्ष 2021 से सभी पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है।
- एकलव्य पुरस्कार : वर्ष 2022 के एकलव्य पुरस्कार के लिये भोपाल के आस्था दांगी (क्याकिंग-केनोइंग), अमन सिंह बिष्ट (बॉक्सिंग), प्रज्ञा सिंह (फेंसिंग), आशी चौकसे (शूटिंग) और सौम्या तिवारी (क्रिकेट), राजगढ़ की रितिका दांगी (सेलिंग), देवास के अभिषेक परिहार (सॉफ्ट-टेनिस), इंदौर की पलक शर्मा (तैराकी), ग्वालियर की खुशबू (हॉकी), उज्जैन के दीपेश लश्करी (जिम्नास्टिक) और इंद्रजीत नागर को (मलखंब) खेल में एकलव्य पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है।

नोट :

- विक्रम पुरस्कार : वर्ष 2022 के विक्रम पुरस्कारों के लिये भोपाल के राजू सिंह (घुड़सवारी), देवास के आदित्य दुबे (सॉफ्ट-टेनिस), सीहोर की नीतू वर्मा (क्याकिंग-केनोइंग), अशोकनगर के भूरक्षा दुबे (वूशु), रायसेन की प्रगति दुबे (शूटिंग), इंदौर के सुबोध चौरसिया (सॉफ्टबॉल) एवं आवेश खान को (क्रिकेट), ग्वालियर के नीरज राणा (हॉकी) तथा धनंजय दुबे (टेनिस) (दिव्यांग वर्ग में) तथा उज्जैन के राजवीर सिंह पंवार के नामों की घोषणा हुई है।
- विश्वामित्र पुरस्कार: वर्ष 2022 में विश्वामित्र पुरस्कार के लिये भोपाल की बैडमिंटन प्रशिक्षक रश्मि मालवीय का चयन किया गया है।
- लाइफटाइम अचीवमेंट ऑवर्ड: वर्ष 2022 में राज्य स्तरीय लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की श्रेणी में इंदौर के अनिल धूपर (टेनिस) का चयन किया गया है।

प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान तीन चरणों में

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) मोहम्मद सुलेमान ने वल्लभ भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के समस्त ज़िलों में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान तथा यू-विन (U-WIN) पोर्टल की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान तीन चरणों में संचालित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान तीन चरणों (7 से 12 अगस्त, 11 से 16 सितंबर एवं 9 से 14 अक्टूबर, 2023) में संचालित किया जाएगा।
- सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान में टीकाकरण में छूटे हुए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाना है।
- अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी वैक्सीनेटर को क्रियाशील करते हुए शत-प्रतिशत टीकाकरण किये जाने के निर्देश दिये।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार यू-विन पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त छूटे हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को चिह्नित कर माइक्रोप्लानिंग कर उनका टीकाकरण किया जाए।
- एसीएस ने निर्देश दिये कि संस्थागत डिलीवरी पॉइंट पर टीकाकरण के लिये चिह्नित सभी एएनएम संवर्ग को आईएमआई की सफलता के लिये निर्देशित करे। वैक्सीनेटर के रूप में एएनएम अग्रिम तीन चरणों के 6 कार्यदिवसों में टीकाकरण सेवाएँ देंगे।

नोट :

एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 'उन्मेष'

चर्चा में क्यों ?

3-6 अगस्त, 2023 तक भोपाल के रवींद्र भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर साहित्य को जन-जन तक पहुँचाने, साहित्य सृजन और संरक्षण करने की प्रतिज्ञा के साथ एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 'उन्मेष'का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- साहित्य उत्सव उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्त्वावधान में इसका आयोजन किया गया।
- इस आयोजन में दिन में साहित्य से जुड़ी एक्टिविटीज हुई तो शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुति का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- इस साहित्य उत्सव में 75 से अधिक कार्यक्रमों में 100 भाषाओं के 575 से ज़्यादा लेखकों ने सहभागिता की। 13 अन्य देशों के लेखक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
- विदित है कि उन्मेष का यह दूसरा संस्करण है। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव के साथ ही संगीत नाटक अकादमी उत्कर्ष शीर्षक से लोक और जनजातीय प्रदर्शन कलाओं का राष्ट्रीय उत्सव भी किया गया।
- इसमें कविता, कहानी पाठ के अलावा भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय भक्ति साहित्य, सागर साहित्य, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारतीय नाटकों में अलगाव का सिद्धांत, विविधता में एकता, भारत की सौम्य शक्ति, सिनेमा और साहित्य, विदेशी भाषाओं में भारतीय साहित्य का प्रचार-प्रसार, चिकित्सकों का साहित्य, साहित्य और प्रकृति, मशीनों का उदय, लेखकविहीन साहित्य, रचनात्मक बढ़ाने वाली शिक्षा जैसी गतिविधियाँ हुई।

नोट :

आरडीएसएस के तहत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर ज़िले के ईमलीखेड़ा में ऊर्जीकृत

चर्चा में क्यों ?

4 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में ऊर्जा मंत्रालय के लिये प्रारंभ रिवेम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत देश का पहला 33/11 केवी का बिजली ग्रिड इंदौर ज़िले के सांवेर तहसील के ईमलीखेड़ा में पूर्ण होकर ऊर्जीकृत हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- पाँच एमवीए क्षमता का उक्त ग्रिड तीन करोड़ की लागत का है। इससे आठ हज़ार बिजली उपभोक्ता एवं पाँच गाँवों की पच्चीस हज़ार जनता को उच्च गुणवत्तायुक्त चौबीस घंटे बिजली मिलेगी।
- अमित तोमर ने बताया कि इस ग्रिड के लिये भूमि-पूजन फरवरी 2023 में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया था। करीब पाँच माह में उक्त ग्रिड तैयार होकर ऊर्जीकृत हो गया है।
- ग्रिड के निर्माण की विद्युत उपकरण सामग्री, पावर ट्रांसफार्मर, वीसीबी, केबल, कंडक्टर आदि राष्ट्रीय स्तर की एनएबीएल में परीक्षण उपरांत ही उपयोग में लाए गए।
- पहली बार ग्रिड में पैंथर कंडक्टर का उपयोग किया गया है, जो परंपरागत कंडक्टर से करीब दोगुनी क्षमता का है। कंपनी क्षेत्र में इस तरह के 97 ग्रिडों का कार्य विभिन्न चरणों में क्रियाशील है।
- आरडीएसएस के तहत बनाए जा रहे ग्रिडों एवं संबंधित लाइनों पर कुल 380 करोड़ रुपए व्यय हो रहे हैं। इससे कंपनी क्षेत्र की बिजली वितरण क्षमता करीब 500 एमवीए बढ़ जाएगी।
- ग्रिडों के साथ ही कंडक्टरों की जगह केबल, इंदौर, उज्जैन आदि के चुनिंदा स्थानों पर अंडरग्राउंड केबल, पुराने ग्रिडों का नवीनीकरण एवं क्षमता में बढ़ोतरी, पुराने कंडक्टरों की जगह नए एवं ज्यादा क्षमता के कंडक्टर लगाने, केपेसिटर बैंकों की स्थापना आदि के कार्य भी क्रमबद्ध रूप से किये जा रहे हैं।
- आरडीएसएस के तहत कार्यों की प्रति सप्ताह समीक्षा की जाती है, ताकि कार्य समय पर एवं गुणवत्ता के साथ हो। ग्रिडों के पास वाटर हार्वेस्टिंग के आदेश दिये गए हैं, ताकि ग्रिड के बोरिंग ग्रीष्मकाल में भी चलते रहें और ग्रिड में अर्थिंग के लिये पानी का संकट न आए।

नोट :

रामपुरा-मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना

चर्चा में क्यों ?

7 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच ज़िले के मनासा में विकास पर्व के कार्यक्रम में 1208 करोड़ रुपए की रामपुरा मनासा बृहद् सूक्ष्म दाबयुक्त सिंचाई परियोजना के भूमि-पूजन सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- 1208.89 करोड़ रुपए की रामपुरा-मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना में रामपुरा, मनासा, नीमच एवं जावद तहसील के कुल 215 गाँवों की 65 हज़ार 400 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसके लिये गांधी सागर जलाशय के डूब क्षेत्र पर सेमली आंत्री एवं ग्राम बनडा पर दो पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कर पाईप लाइन डाली जाएगी।
- कुल सिंचाई क्षेत्र को 30-30 हेक्टेयर के चक में तथा प्रत्येक तीस हेक्टेयर चक को 5-5 हेक्टेयर सब चक में विभाजित कर, सिंचाई के लिये जल उपलब्ध करवाया जाएगा।
- किसानों की सुविधा के लिये प्रत्येक तीस हेक्टेयर के चक पर स्वचलित आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किये जाएंगे, जहाँ से किसानों को निर्धारित दाब से निश्चित मात्रा में सिंचाई के लिये जल उपलब्ध हो सकेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शीघ्र ही 3500 करोड़ रुपए लागत की नीमच-जावद सिंचाई योजना भी प्रारंभ की जाएगी।

नोट :

प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन और राज्य सरकार के मध्य हुआ एम.ओ.यू.

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में निवास कार्यालय समत्व में प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन और राज्य शासन की ओर से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मध्य एम.ओ.यू हुआ।

प्रमुख बिंदु

- बच्चों में जन्मजात हृदय विकार का उपचार माता-पिता सरलता से करा सकें और विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध हों, इसी उद्देश्य से प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ राज्य सरकार का एम.ओ.यू. किया गया है।
- इस एम.ओ.यू. के अंतर्गत प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा बाल्यकालीन हृदय रोग से प्रभावित बच्चों का श्री सत्य साई हार्ट अस्पताल अहमदाबाद में नि:शुल्क उपचार कराया जाएगा।
- इसके अंतर्गत अहमदाबाद में स्थापित चिकित्सालय में एक हज़ार बच्चों का इलाज पूर्णत: नि:शुल्क कराया जाएगा, आने-जाने का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
- उल्लेखनीय है कि एक हज़ार जीवित बच्चों में से लगभग 9 बच्चों में जन्मजात हृदय विकार की समस्या रहती है, जिसके उपचार पर एक लाख से पाँच लाख रुपए तक का व्यय आता है। अत: गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिये यह इलाज कठिन हो जाता है। रोग की समय पर पहचान तथा सही उपचार मिलने पर बच्चे अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा बाल हृदय उपचार योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया।
- इस योजना में नारायणा हृदयालय मुंबई, चिरायु अस्पताल भोपाल, अरविंदो अस्पताल इंदौर में बच्चों के उपचार की व्यवस्था की गई।
- विदित है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ दो वर्ष के लिये अनुबंध किया और कुल 117 बच्चों को नि:शुल्क उपचार प्रदान किया गया। अब पुन: एम.ओ.यू. किया गया है।

नोट :

उज्जैन में बनेगा देश का पहला यूनिटी मॉल

चर्चा में क्यों ?

10 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा। इसके निर्माण के लिये वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 284 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- यह स्वीकृति भारत सरकार की 'स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर केपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24' के तहत दी गई है।
- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने यूनिटी मॉल का निर्माण समय-सीमा में करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं।
- यूनिटी मॉल वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट, जी.आई. प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिये वन स्टाप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश में सभी ज़िलों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये दुकानें रहेंगी।
- यूनिटी मॉल में अन्य राज्यों के प्रमुख उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे। यहाँ सभागार, खाने के स्टॉल और गार्डन भी रहेगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रदेश में एक यूनिटी मॉल का निर्माण होना है। भारत सरकार से पहली स्वीकृति मध्य प्रदेश को मिली है।

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग और एनआईडी के बीच हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश में एक ज़िला एक उत्पाद के तहत छतरपुर ज़िले के प्रसिद्ध फर्नीचर उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध करवाने के लिये प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग और नेशनल डिज़ाइन संस्थान (एनआईडी) के बीच एमओयू हुआ।

प्रमुख बिंदु

- एमएसएमई विभाग के सचिव-सह-आयुक्त पी. नरहरि एवं एनआईडी, भोपाल के निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार द्वारा इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए।
- एमएसएमई विभाग के सचिव-सह-आयुक्त ने कहा कि इस अनुबंध के बाद छतरपुर के फर्नीचर डिजाइन और उत्पाद को नया मंच मिलेगा।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि 'एक ज़िला एक उत्पाद योजना'की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। यह योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है।
- इस योजना को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य सभी राज्यों के पास अपना एक प्रोडक्ट ऐसा होगा, जिससे उसे ज़िले व उस राज्य में उसकी अपनी एक अलग पहचान मिलेगी।
- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 'एक ज़िला एक उत्पाद'के लिये सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये मंजूरी दे दी है।

नवगठित मऊगंज ज़िला के ज़िलाधीश (कलेक्टर) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) की हुई पद-स्थापना

चर्चा में क्यों ?

13 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने नवगठित ज़िला मऊगंज के प्रथम ज़िलाधीश (कलेक्टर) अजय श्रीवास्तव और प्रथम पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में वीरेंद्र जैन की नियुक्ति की है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि अजय श्रीवास्तव 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं, जो अपर आयुक्त, आदिवासी विकास एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) के पद में शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहें थे, अब नवगठित ज़िले के पहले कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएँ देंगे।
- इनसे पहले सोनिया मीना को ज़िला मऊगंज कलेक्टर पदस्थ करने का आदेश राज्य शासन ने जारी किया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था।
- इसी तरह वीरेंद्र जैन IPS (DD-96) को नए ज़िले मऊगंज का पुलिस अधीक्षक (एसपी) के तौर पर स्थानांतरित किया गया है। वीरेंद्र जैन वर्तमान में छिंदवाड़ा में सेनानी 8वीं वाहिनी विसबल में पदस्थ हैं।
- विदित है कि 4 मार्च, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज को नया ज़िला बनाने की घोषणा की थी। मऊगंज आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश का 53वाँ ज़िला बन गया है।
- मऊगंज को रीवा से अलग करके ज़िला बनाया गया है और इसका ज़िला मुख्यालय मऊगंज शहर में स्थित होगा। साथ ही 15 अगस्त को मऊगंज ज़िला मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
- मऊगंज ज़िले का गठन मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा के तहत किया गया है। इस बदलाव के संबंध में एक राजपत्र (गजट) प्रकाशित किया गया है।
- प्रारंभिक रूप में रीवा ज़िले की तीन तहसीलें- मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमना मऊगंज ज़िले का हिस्सा होंगी। बाद में देवतालाब को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

नोट :

बालाघाट को मिला स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

12 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के महिला-बाल विकास विभाग के बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर को अपने बेहतर प्रदर्शन के लिये स्कॉच अवॉर्ड के ऑर्डर ऑफ मेरिट-2023 से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- बालाघाट वन स्टॉप सेंटर वर्ष 2018 से ज़िले में सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान कर रहा है।
- इसके साथ ही पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें मनोवैज्ञानिक परामर्श, एफआईआर, पुलिस चिकित्सा, विधिक और न्यायालयीन आदि सहायता प्रमुख हैं।
- बालाघाट ज़िले में दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं को भी सखी सेंटर का लाभ मिले, इसके लिये ज़िला प्रशासन के प्रयासों से दूसरा वन स्टॉप सेंटर ज़िले की बैहर तहसील में संचालित किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 से स्थापित स्कॉच पुरस्कार एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
- यह उन लोगों, परियोजना और संस्थानों को मान्यता देता है, जो देश को बेहतर बनाने के लिये अतिरिक्त प्रयास करते हैं।
- इस पुरस्कार के लिये देशभर से नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। इसमें से 3 चरणों में प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन के बाद यह चयन हुआ है।
- यह वन स्टॉप सेंटर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा और ज़िला कार्यक्रम अधिकारी वंदना धूमकेती के मार्गदर्शन में संचालित हुआ है।

प्रधानमंत्री ने रखी संत रविदास मंदिर की आधारशिला

चर्चा में क्यों ?

12 अगस्त, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़तुमा सागर में 11 एकड़ भूमि पर लगभग100 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेने वाले संत शिरोमणि श्री रविदास जी के स्मारक और मंदिर का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमिपूजन कर शिलान्यास किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उन्होंने शिला-पटिका का अनावरण भी किया और मंदिर की प्रतिकृति का अवलोकन किया।
- इसी के साथ प्रदेश के पाँच स्थानों से प्रारंभ की गई समरसता यात्रा का भी समापन हुआ।
- उल्लेखनीय है कि फरवरी माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समरसता के प्रणेता श्री संत रविदास जी के भव्य और दिव्य रूप में स्मारक एवं मंदिर निर्माण कराने की घोषणा की थी।
- प्रधानमंत्री द्वारा किये गए शिलान्यास के बाद अब यहाँ भव्य और अलौकिक मंदिर बनेगा। यह मंदिर नागर शैली में 10000 वर्ग फीट में बनेगा। यहाँ इंटरप्रिटेशन म्यूजियम भी बनेगा।
- संस्कृति और रचनात्मक के साथ संत रविदास के कृतित्व-व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय भी इस परिसर में बनेगा।
- संग्रहालय में चार गैलरी बनेंगी, जिनमें भक्ति मार्ग, निर्गुण पंथ में योगदान, संत जी का दर्शन और उनके साहित्य, समरसता का विवरण भी रहेगा।
- इसके अलावा संगत हाल, जल कुंड, भक्त निवास भी बनेगा, जो आध्यात्मिक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। भक्त निवास में देश-विदेश से संत रविदास के अनुयायी और अध्येता आएंगे, जिन्हें संत जी के जीवन से प्रेरणा मिलेगी।
- वास्तु और विन्यास के अनुसार संत रविदास जी का मंदिर अध्यात्म कला संग्रहालय भी होगा, जो श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अभूतपूर्व स्थल होगा। दार्शनिक एवं अध्येता और जिज्ञासु भी देश-विदेश से आएंगे। संत रविदास जी का कृतित्व-व्यक्तित्व और दर्शन पूरी दुनिया के लिये प्रेरणादायी होगा।
- उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई, 2023 से सागर ज़िले में संत रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिये पाँच अलग-अलग स्थानों (नीमच, मांडव ज़िला धार, श्योपुर, बालाघाट और सिंगरौली) से एक साथ यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा का व्यवस्थित समापन हुआ।
- इसके पहले प्रदेश के हर गाँव से मिट्टी और सभी विकास खंडों की 313 नदियों से सांकेतिक जल लेकर यात्रा सागर पहुँची। प्रदेश के ज़िलों से होकर संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा गुज़री। मुख्य यात्राओं के साथ 1661 उप यात्रियों द्वारा भी कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान 352 जन-संवाद हुए। यात्रा के 5 रूटों में 25 लाख से अधिक लोग शामिल हुए।
- मध्य प्रदेश के 20 हज़ार 641 गांवों की मिट्टी और 313 नदियों के सांकेतिक जल एकत्र कर सागर पहुँची समरसता यात्रा के दौरान संत रविदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित 10 रथ निरंतर चलते रहे।

नोट :

प्रदेश के शासकीय सेवकों को 35 वर्ष की सेवा पर चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलेगा

चर्चा में क्यों ?

14 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने प्रदेश की सिविल सेवाओं के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है, उनमें 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान देय होने के संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- राज्य शासन के आदेश के अनुसार ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति की तिथि से तीन पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 01.07.2023 या इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।
- राज्य के शासकीय सेवक को चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिये सेवा अवधि की गणना, प्रतियोगी/चयन परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन के अंतर्गत किसी सीधी भर्ती के पद पर प्रथमवार किये गए कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी।
- उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, जो कि विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिये निर्धारित हैं।
- राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें विशिष्ट योजना के अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मंत्रि-परिषद से पृथक् आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- यदि किसी संवर्ग को परिशिष्ट-। के अनुसार निर्धारित चतुर्थ समयमान वेतनमान के तुल्य अथवा अधिक लेवल का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, तब उन्हें वर्तमान प्राप्त लेवल का वेतनमान ही प्राप्त होता रहेगा।
- मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को चतुर्थ समयमान वेतनमान के अंतर्गत मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवें वेतनमान के अनुसार) मेट्रिक्स लेवल वर्ग-अ प्रथम श्रेणी, वर्ग-ब द्वितीय श्रेणी, वर्ग-स तृतीय श्रेणी, कार्यपालिका एवं सचिवीय सेवाएँ एवं वर्ग- द चतुर्थ श्रेणी है।

सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ सर्वाधिक कम करने में नर्मदापुरम् वृत्त प्रथम

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2023 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के नर्मदापुरम् वृत्त को कंपनी कार्यक्षेत्र में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटीएंडसी) में सर्वाधिक कमी करने पर प्रशस्ति-पत्र एवं पदक से पुरस्कृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह पुरस्कार कंपनी मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में नर्मदापुरम् वृत्त के महाप्रबंधक बी.बी.एस.परिहार को कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया।
- गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कंपनी कार्यक्षेत्र में एलटी श्रेणी में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में सर्वाधिक कमी करने वाले वृत्त/संभाग को पुरस्कृत किया जाता है।
- इसी अनुक्रम में संचारण संधारण वृत्त नर्मदापुरम् द्वारा विशेष प्रयासों से गत वर्ष 2021-22 में एटीएंडसी हानि 23.18 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022-23 में 18.65 प्रतिशत कम कर कंपनी कार्यक्षेत्र में सर्वाधिक कमी लगभग 4.53 प्रतिशत कर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है।
- इसी प्रकार सोहागपुर संभाग द्वारा विशेष प्रयासों से गत वर्ष 2021-22 में एटीएंडसी हानि 27.42 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022-23 में 17.77 प्रतिशत कम कर सर्वाधिक कमी लगभग 9.64 प्रतिशत कर कंपनी कार्यक्षेत्र के समस्त संभागों में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है।

नोट :

प्रदेश में मदरसा से संबंधित 4 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी में अधिसूचित

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंधित 4 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इन सेवाओं में मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिये बोर्ड से मान्यता, मदरसा मान्यता का नवीनीकरण, मदरसा संचालन समिति का पंजीयन और मदरसा संचालन समिति का नवीनीकरण सेवा शामिल हैं।
- प्रदेश में बोर्ड से मान्यताप्राप्त 1755 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें 6 हज़ार 155 शिक्षक कार्यरत् हैं। इन मदरसों में 1 लाख 1 हज़ार 454 बच्चे (52 हज़ार 12 बालक और 49 हज़ार 442 बालिकाएँ) अध्ययनरत् हैं।
- मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

आरडीएसएस के तहत देश का पहला ग्रिड लोकार्पित

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2023 को रिवेंप्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत देश में सबसे पहले तैयार किये गए इंदौर ज़िले के इमलीखेड़ा में अत्याधुनिक 33/11 केवी के बिजली ग्रिड का लोकार्पण हुआ।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश के जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने ग्रिड का लोकार्पण किया।
- पाँच एमवीए क्षमता का उक्त ग्रिड तीन करोड़ की लागत का है। इससे आठ हज़ार बिजली उपभोक्ता एवं पाँच गाँवों की पच्चीस हज़ार जनता को उच्च गुणवत्तायुक्त चौबीस घंटे बिजली मिलेगी।

नोट :

- विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में ऊर्जा मंत्रालय के लिये प्रारंभ रिवेमुंड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत देश का पहला 33/11 केवी का बिजली ग्रिड हाल ही में इंदौर ज़िले के सांवेर तहसील के इमलीखेड़ा में पूर्ण होकर ऊर्जीकृत हुआ है।
- इस ग्रिड के लिये भूमि-पूजन फरवरी 2023 में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया था।
- ग्रिड के निर्माण की विद्युत उपकरण सामग्री, पावर ट्रांसफार्मर, वीसीबी, केबल, कंडक्टर आदि राष्ट्रीय स्तर की एनएबीएल में परीक्षण के उपरांत ही उपयोग में लाए गए हैं।
- पहली बार ग्रिड में पैंथर कंडक्टर का उपयोग किया गया है, जो परंपरागत कंडक्टर से करीब दोगुनी क्षमता का है। कंपनी क्षेत्र में इस तरह के 97 ग्रिडों का कार्य विभिन्न चरणों में क्रियाशील है।

मध्य प्रदेश की 100 साल पुरानी संगीत धरोहर मैहर बैंड होगी पुनरुज्जीवित

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 100 वर्ष पुरानी संगीत धरोहर मैहर बैंड को पुनरुज्जीवित किया जाएगा। गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित मैहर बैंड को 'मैहर बैंड गुरुकुल'के रूप में संचालित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- गुरुकुल में बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान की 150 दुर्लभ बंदिशों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैहर संगीत महाविद्यालय भवन मैहर में ही संचालित गुरुकुल में प्रशिक्षणार्थी मैहर वाद्यवृंद में प्रयुक्त होने वाले सभी वाद्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
- विदित है कि संगीत कला क्षेत्र का अनूठा और अद्वितीय वाद्यवृंद मैहर बैंड संगीत परंपरा का अनुपम उदाहरण है, जिसे पुनरुज्जीवित कर संगीत की प्राचीन परंपरा को सहेजकर आगे बढ़ने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।

नोट :

- मंत्री सुश्री ठाकुर ने बताया कि गुरुकुल में प्रशिक्षण का सत्र अधिकतम 2 वर्ष का होगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को 10 हज़ार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। मैहर बैंड के सेवानिवृत्त 5 संगीतकारों को प्रशिक्षण के लिये 37 हज़ार 500 रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। प्रारंभिक सत्र में 20 प्रशिक्षणार्थियों को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- मंत्री सुश्री ठाकुर ने बताया कि गुरुकुल के द्वारा न केवल मैहर बैंड को पुनरुज्जीवित किया जाएगा बल्कि मैहर वाद्यवृंद में प्रस्तुत होने वाले वाद्यों का प्रशिक्षण देकर अनेक श्रेणी के मैहर बैंड भी स्थापित किये जा सकेंगे।

नोट :

16 सीएम राइज़ स्कूल, 19 कन्या शिक्षा परिसर का 1129 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा 16 सीएम राइज़ स्कूल भवनों एवं 19 कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्माण कार्य के लिये 1129 करोड़ 66 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- बैतूल में 4, मंडला एवं अनूपपुर में 3-3, धार में 2 और बड़वानी, श्योपुर, सीधी एवं अलीराजपुर में एक-एक सीएम राइज़ स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
- इसी प्रकार सिवनी में 3, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं अनूपपुर में 2-2 और सीधी, इंदौर, जबलपुर, धार, उमरिया, शहडोल, सीहोर एवं खरगोन में एक-एक कन्या शिक्षा परिसर भवन का निर्माण किया जाएगा।
- सीएम राइज़ योजनांतर्गत 540 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से 16 स्कूल भवन निर्माण कार्यों में से 10 की निर्माण एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग तथा 6 कार्यों की निर्माण एजेंसी भवन विकास निगम होगी।
- 589 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से 19 कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण कार्यों में से 7 कार्यों की निर्माण एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, 7 कार्यों की भवन विकास निगम एवं 5 कार्यों की निर्माण एजेंसी पुलिस आवास गृह एवं अधोसंरचना विकास निगम को बनाए जाने की स्वीकृति जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।

हरदा बना सबसे कम वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने वाला वृत्त

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2023 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हरदा वृत्त को कंपनी कार्यक्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मर की असफल दर में सर्वाधिक कमी करने पर प्रशस्ति-पत्र एवं पदक से पुरस्कृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह पुरस्कार कंपनी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हरदा वृत्त के महाप्रबंधक अनूप सक्सेना को कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा द्वारा दिया गया।
- गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कंपनी कार्यक्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मर की असफल दर कम करने वाले वृत्त को पुरस्कृत किया जाता है। हरदा वृत्त द्वारा विशेष प्रयासों से वितरण ट्रांसफार्मर की असफलता में गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में 2.4 प्रतिशत की कमी लाए जाने का कार्य किया जो कि कंपनी में सबसे कम है।
- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के शहर वृत्त ग्वालियर को कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत दुर्घटना दर में सर्वाधिक कमी करने पर प्रशस्ति-पत्र एवं पदक से पुरस्कृत किया गया है।
- विदित है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत दुर्घटना की दर में सर्वाधिक कमी करने वाले वृत्त को पुरस्कृत किया जाता है। ग्वालियर शहर वृत्त द्वारा सुरक्षा संबंधी विशेष प्रयासों से गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में दुर्घटनाएँ 83.33 प्रतिशत कम हुईं।
- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के ग्वालियर क्षेत्र के भिंड वृत्त में ऐंतहार वितरण केंद्र को ग्वालियर क्षेत्र में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटी एंड सी) में सर्वाधिक कमी करने पर स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया है।
- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के भोपाल क्षेत्र के बैतूल वृत्त में घाटबिरोली वितरण केंद्र को भोपाल क्षेत्र में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटी एंड सी) में सर्वाधिक कमी करने पर स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया है।
- बैतूल वृत्त के घाटबिरोली वितरण केंद्र द्वारा विशेष प्रयासों से एटी एंड सी हानियों में गत वर्ष की तुलना में 5.69 प्रतिशत की कमी कर भोपाल क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

नोट :

केंद्रीय गृह मंत्री ने जारी किया मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड

चर्चा में क्यों ?

- 20 अगस्त, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में गरीब कल्याण महाअभियान में मध्य प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड (2003-2023) को जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में गरीब कल्याण महा अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दो दशक (2003-2023) में हुए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किये जाने के अवसर पर मध्य प्रदेश में विकास आयामों पर केंद्रित फिल्म प्रदर्शित की गई।
- केंद्र सरकार के गत 9 वर्ष के कार्यकाल में हुए उल्लेखनीय कार्यों एवं उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं पर आधारित गीत लॉन्च किया गया।
- केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश की उपलब्धियों का विषयवार उल्लेख-
  - देश में यदि गत दस वर्ष में 10 प्रतिशत आबादी गरीबी के चक्र से बाहर निकली है तो उसमें मध्य प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है।
  - मध्य प्रदेश के बजट का आकार वर्ष 2002 में 23 हज़ार 100 करोड़ रुपए था। अब यह 3 लाख 14 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक है।
  - मध्य प्रदेश में शिक्षा का बजट 2556 करोड़ रुपए से बढ़कर 38 हज़ार करोड़ रुपए हुआ है।
  - मध्य प्रदेश में पूर्व सरकार के समय स्वास्थ्य का बजट सिर्फ 580 करोड़ रुपए था, जो अब 16 हज़ार करोड़ रुपए है। इसमें आयुष्मान भारत योजना शामिल नहीं है।
  - सर्व शिक्षा अभियान में सिर्फ 844 रुपए की राशि खर्च होती थी, अब लगभग 7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
  - अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण पर भी बजट में वृद्धि हुई है। पहले जहाँ 1056 करोड़ रुपए की राशि खर्च होती थी, अब 64 हज़ार 390 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
  - सर्व शिक्षा अभियान में सिर्फ 844 रुपए की राशि खर्च होती थी, अब लगभग 7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
  - मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय पहले 11 हज़ार 700 रुपए थी, जो अब बढ़कर एक लाख 40 हज़ार रुपए हो गई है।
  - एमएसएमई सेक्टर में साल भर में 4 हज़ार 299 उद्योगों के पंजीयन होते थे। अब इनकी संख्या 3 लाख 61 हज़ार है।
  - सड़क निर्माण में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है। पहले सिर्फ 60 हज़ार किलोमीटर सड़कें थीं। अब प्रदेश में 5 लाख 10 हज़ार किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कें हैं, जो आठ गुना से भी ज़्यादा हैं। एनएच सड़कों की लंबाई 4800 से बढ़कर 13 हज़ार किलोमीटर हो गई।
  - कृषि क्षेत्र में कृषि विकास दर साढ़े छह गुना बढ़ गई है। गेंहूँ खरीदी 4 लाख 38 हज़ार मीट्रिक टन से 70 लाख 96 हज़ार मीट्रिक टन और धान खरीदी 0.95 हज़ार मीट्रिक टन से बढ़कर 46 लाख 30 हज़ार मीट्रिक टन हो गई है। प्रदेश में 90 लाख से अधिक किसानों को 19 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक लाभ दिये गए हैं।
  - मध्य प्रदेश में नि:शुल्क राशन वितरण का लाभ सिर्फ 52 लाख परिवारों को मिलता था, जो करीब सवा करोड़ लोगों को मिल रहा है।
  - प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 4 से बढ़कर 24 तक हो गई है। मेडिकल सीटें 620 थीं जो अब 4 हज़ार से ज्यादा हैं।
  - एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय बिल्कुल नहीं थे। इनकी संख्या अब 63 है। आईटीआई की संख्या 159 से बढ़कर 1514 हो गई है।
  - पर्यटन क्षेत्र में सड़कों के बनने से पर्यटक संख्या बढ़ी है। एक समय सिर्फ 64 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष आते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 9 करोड़ हो गई है।
  - प्रदेश में तीन शहरों- रीवा, ग्वालियर और जबलपुर में एयरपोर्ट विकास और टर्मिनल निर्माण के कार्य हो रहे हैं। इंदौर को दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर में शामिल किया गया है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाएँ क्रियान्वित हो रही हैं।
  - प्रदेश की ऊर्जा क्षमता 29 हज़ार मेगावाट से भी अधिक है। सिंचाई साधनों के विस्तार से 47 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचित हो रहा है।

नोट :

- प्रदेश में 46 लाख से अधिक बालिकाओं को 'लाडली लक्ष्मी योजना' और 53 लाख से अधिक बहनों को स्वसहायता समूहों से जोड़कर लाभान्वित किया गया है।
- प्रदेश में जनजातीय समाज के हित में पेसा कानून लागू करने और जनजातीय संस्कृति दिखाने वाले संग्रहालय की स्थापना की जा रही है।
- मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश के लिये फेवरेट डेस्टिनेशन बना है।
- खंडवा ज़िले में ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ रुपए लागत से विद्युत उत्पादन इकाई प्रारंभ की जा रही है।
- प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की पहल हुई है।
- प्रदेश की आर्थिक विकास दर 16 प्रतिशत से अधिक है

नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आयोजित हुआ फूड फेस्टिवल

चर्चा में क्यों ?

- 18-20 अगस्त, 2023 तक दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल' का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- आवासीय आयुक्त पंकज राग और मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री आईसीपी केसरी ने फेस्टिवल का शुभारंभ किया।
- फेस्टिवल में मध्य प्रदेश के विशेष व्यंजन, जैसे- भुट्टे की किस, इंदौरी पोहा, सेव भाजी, बेसन गटो, मटर निमोना, दाल बाफला, पिलाफ, मटन सैलाना और भोपाली मुर्ग रेजाला के साथ-साथ मालवा थाली, बुंदेलखंड थाली और मध्य प्रदेश स्पेशल थाली का स्वाद आगंतुकों ने लिया।
- श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिये मिलेट खीर, चूरमा लड्डू और रागी हलवा जैसे व्यंजन भी उपलब्ध रहे। सांची के दुग्ध उत्पाद की बिक्री और प्रदेश के हस्तशिल्प एवं खादी उत्पादों की प्रदर्शनी भी फेस्टिवल में लगाई गई थी।

नोट :

- विदित है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से 'आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल'प्रतिभागी राज्यों के नई दिल्ली स्थित राज्य सदनों/भवनों में कर रहा है। इसका उद्देश्य पाक-कला के क्षेत्र में भारत की समृद्ध विविधता का उत्सव मनाना है।

नोट :

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

- 18 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' में संशोधन आदेश जारी किया गया। बीपीएल कार्डधारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, जिनके पिता/पालक की आय 8 लाख रुपए तक हो, को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- आदेशानुसार ऐसे विद्यार्थी, जिनके पिता/पालक की आय 8 लाख रुपए से कम हो, वे योजना के लिये पात्र होंगे, परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है तथा वह बीपीएल कार्डधारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हों, को विशेष प्रकरण मानते हुए इनके संबंध में विभागीय समन्वय में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेंगे।
- ऐसे विद्यार्थियों, जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के बाद यथानिर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा 8, लाख रुपए से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा

मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री ने दतिया में नवीन एयरपोर्ट का किया शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

21 अगस्त, 2023 को केंद्रीय नागरिक विमानन एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में 29 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत के नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया के बसई में महाविद्यालय खोलने, नगर पंचायत बनाने के साथ-साथ ग्राम खिरिया फैजुल्ला का नाम खिरिया सरकार करने के लिये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहनों के खाते में प्रति माह 1 हज़ार रुपए की राशि पहुँच रही है, जो धीरे-धीरे बढ़ाकर प्रतिमाह 3 हज़ार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत माँ पीतांबरा की धरा दतिया से ही की गई थी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बेटा-बेटियों की फीस अब सरकार भरेगी। इसी 22 अगस्त से युवाओं को रोज़गार देने के साथ स्टाईपेंड देने हेतु 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना'शुरू की जा रही है, जिसमें आईटीआई एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं को 8 से 10 हज़ार रुपए का स्टाईपेंड दिया जाएगा।
- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दतिया में नवीन एयरपोर्ट के बन जाने पर 19 सीटर विमान उतरने की सुविधा प्राप्त होगी। एयरपोर्ट से खजुराहो एवं भोपाल के लिये हवाई सेवाएँ भी शुरू की जाएगी। ग्वालियर का नवीन एयरपोर्ट भी 15 माह में तैयार होगा।
- सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ धार्मिक क्षेत्रों में भी विमानों की सेवाएँ देना शुरू कर दिया गया है। श्रीनगर-जम्मू में भी नए एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 22 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन'में हुई, जिसमें अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से देय मंहगाई राहत की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई है। मंत्री परिषद के निर्णय के अनुसार महँगाई राहत की दर सातवें वेतनमान के अंतर्गत 42% और छठवें वेतनमान के अंतर्गत 221% की गई है। इस निर्णय से शासन पर अनुमानित 410 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार संभावित है ।
- मंत्रि-परिषद द्वारा ज़िला बैतूल में नवीन अनुविभाग आमला के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

नोट :

- मंत्रि-परिषद द्वारा ज़िला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। ज़िला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 13 हज़ार 500 रुपए और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 4500 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा रबी वर्ष 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24) एवं आगामी दो वर्षों में भारत सरकार के प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों तथा ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
- साथ ही रबी वर्ष 2021-22 (रबी विपणन वर्ष 2022-23) में प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चना के लिये 8 लाख 71 हज़ार 100 मीट्रिक टन एवं मसूर के लिये 1 लाख 67 हज़ार 130 मीट्रिक टन तथा सरसों के लिये 3 लाख 48 हज़ार 935 मीट्रिक टन के नियत उपार्जन लक्ष्य के भीतर चने के 8 लाख 01 हज़ार 662.86 मीट्रिक टन का उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया

'मध्य प्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति 2023' की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

- 22 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा आत्म-समर्पण करने वाले नक्सलियों को लाभकारी रोज़गार और उद्यमशीलता के अवसरों को प्रदान करने के उद्देश्य से 'मध्य प्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति 2023' स्वीकृत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति राज्य में उत्पन्न वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य हिंसा का रास्ता त्यागकर स्वेच्छा से आत्म-समर्पण करने वालों को मुख्यधारा में शामिल करना है।
- म.प्र. नक्सली आत्म-समर्पण, पुनर्वास-सह-राहत नीति 2023 में नक्सली/नक्सलवादी एवं आत्म-समर्पणकर्त्ता को स्पष्ट एवं वृहत् रूप से परिभाषित किया गया है। आत्म-समर्पणकर्त्ता के निर्धारण के लिये निश्चित मापदंड निर्धारित किये गए हैं।
- आत्म-समर्पणकर्त्ता को लाभ देने के लिये राज्यस्तरीय जाँच समिति का प्रावधान किया गया है। (पूर्व नीति में आत्म-समर्पणकर्त्ता को लाभ देने के लिये राज्यस्तरीय जाँच समिति की अवधारणा नहीं है।)
- आत्म-समर्पण प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिये सक्षम अधिकारियों की परिधि बढ़ाई गई है, जैसे- आत्म-समर्पणकर्त्ता स्वेच्छा से किसी पुलिस अधिकारी, कार्यपालिक दंडाधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सहायक सेनानी से अन्यून रैंक के अधिकारी (जहाँ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात है) या राज्य सरकार द्वारा नामांकित अधिकारी के समक्ष आत्म-समर्पण कर सकेगा। (पूर्व नीति में आत्म-समर्पण के लिये पुलिस अधीक्षक को माध्यम निर्धारित किया गया है।)
- नक्सली द्वारा आत्म-समर्पण किये जाने के पश्चात् की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
- आत्म-समर्पणकर्त्ता द्वारा शस्त्रों के साथ समर्पण किये जाने पर अनुग्रह राशि का स्पष्ट वर्गीकरण किया गया है।
- आत्म-समर्पणकर्त्ता ने यदि शस्त्रों (शस्त्र चालू हालत स्थिति में हो तो) के साथ समर्पण किया है तो ऐसी स्थिति में 07 श्रेणियों में शस्त्रों का वर्गीकरण किया जाकर 20 हज़ार से 4 लाख 50 हज़ार रुपए तक अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है। (पूर्व नीति में इस विषय पर अनुग्रह राशि का स्पष्ट वर्णन नहीं है।)
- आत्म-समर्पणकर्त्ता को गृह निर्माण के लिये 1 लाख 50 हज़ार रुपए अनुदान का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। (पूर्व नीति में इंदिरा आवास योजना में अनुदान की राशि उपलब्ध कराना प्रावधानित है।)
- आत्म-समर्पणकर्त्ता को विवाह के लिये 50 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। (पूर्व नीति में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।)
- आत्म-समर्पणकर्त्ता को बिना शर्त 5 लाख रुपए प्रोत्साहन अथवा इनाम राशि प्रदान करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। (पूर्व नीति में आत्म-समर्पणकर्त्ता के नक्सल विरोधी अभियान में सहयोग के आधार पर घोषित इनाम राशि दिये जाने का प्रावधान है।)

नोट :

- आत्म-समर्पणकर्त्ता को अचल संपत्ति /जमीन क्रय के लिये 20 लाख रुपए अनुदान राशि का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। (पूर्व नीति में अनुदान राशि प्रावधानित नहीं है, केवल गरीबी रेखा के नीचे आने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों को भू-आवंटन का प्रावधान किया गया गया है।)
- आत्म-समर्पणकर्त्ता के शिक्षण के लिये 1 लाख 50 हज़ार रुपए का प्रावधान किया गया है। (पूर्व नीति में अनुदान राशि प्रावधानित नहीं है, शासकीय योजनाओं में अस्पष्ट प्रावधान किये गए हैं।)
- आत्म-समर्पणकर्त्ता की उपयोगिता के आधार पर गोपनीय सैनिक अथवा उसके सहयोग से नक्सल उन्मूलन अभियान में सफलता प्राप्त होने पर पुलिस विभाग में शासकीय नौकरी प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। (पूर्व नीति में शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखने पर उसे नियुक्ति दिये जाने पर विचार किये जाने का प्रावधान है, अन्यथा उसे पात्रता अनुसार होमगार्ड के रूप में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।)
- नक्सल पीड़ित परिवार एवं शारीरिक अक्षमता के संबंध में स्पष्ट एवं बृहद् उल्लेख है।
- हिंसा में व्यक्ति/सुरक्षाकर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है। आम नागरिक को 15 लाख रुपए एवं सुरक्षाकर्मी को 20 लाख रुपए प्रावधानित हैं। (पूर्व नीति में आम व्यक्ति को 1 लाख रुपए एवं सुरक्षाकर्मी को 2 लाख रुपए प्रदान किये जाने का प्रावधान है।)
- नक्सल हिंसा में व्यक्ति/सुरक्षाकर्मी के शारीरिक अक्षम हो जाने पर 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। (पूर्व नीति में स्थायी असमर्थ को 50 हज़ार एवं गंभीर घायल को 10 हज़ार रुपए प्रदान किये जाने का प्रावधान है।)
- मृतक के आश्रित को शासकीय सेवा में लिये जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। (पूर्व नीति में यदि मृतक का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो तथा पात्रता रखने पर नियुक्ति पर विचार किये जाने का प्रावधान है।)
- अचल संपत्ति को क्षति होने की स्थिति में राहत राशि का प्रावधान किया गया है, जैसे- पूरा मकान ध्वस्त होने पर 1 एक 50 हज़ार रुपए तथा आंशिक क्षति होने पर क्षति अनुसार अधिकतम 50 हज़ार रुपए का भुगतान किया जाएगा। (पूर्व नीति में क्षति होने पर कच्चे मकान हेतु 5 हज़ार रुपए एवं पक्के मकान के लिये 15 हज़ार रुपए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।) नक्सलियों के पुनर्वास के लिये समय-सीमा एवं प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया गया है

'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ' योजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 22 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ'योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत युवाओं को काम सिखाने के बदले 8 से 10 हज़ार रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिये जाएंगे। काम सीखने के बाद वे खुद का स्वरोज़गार शुरू कर सकते हैं। साथ ही उद्योगों में परमानेंट जॉब भी मिल सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ' योजना में प्रशिक्षण कंपनियों का पंजीयन 7 जून, 2023 से शुरू किया गया था। अब तक 16 हज़ार 744 कंपनियाँ पंजीकृत हो चुकी हैं। अब तक 70 हज़ार 386 पद प्रकाशित हुए हैं।
- साथ ही इस योजना में युवाओं का रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई, 2023 से प्रारंभ हुआ था। इसमें अब तक 8 लाख 71 हज़ार 330 युवा पंजीकृत हुए और अब तक 15 हज़ार 92 अनुबंध निर्मित हुए हैं।
- इस योजना में 46 क्षेत्रों के 700 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण मिलेगा।
- मुख्यमंत्री सीखो कमाओ 'लर्न एंड अर्न'कार्यक्रम है, जिसमें युवाओं को जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग मिलेगी।
- छात्रों को कार्यक्षेत्र में रहकर अनुभव प्राप्त करने और अपना कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा।
- प्रशिक्षण के साथ ही प्रतिमाह स्टाइपेंड भी मिलेगा, ताकि वे प्रशिक्षण के दौरान अपने खर्च उठा सकें -
  - 12वीं उत्तीर्ण को 8000 रुपए
  - आईटीआई उत्तीर्ण को 8500 रुपए

नोट :

- डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9000 रुपए
- स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को 10000 रुपए

- इस योजना में अभ्यर्थियों को मिलने वाले लाभ
  - उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
    - नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
    - व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड।
    - मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा स्टेट कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का प्रमाणन।
    - नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।
- उद्योगों को मिलने वाले लाभ -
  - इस योजना के माध्यम से उद्योगों को अपनी ज़रूरत के अनुसार युवाओं का कौशल संवर्धन करने का अवसर मिलेगा।
  - प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण प्रदाता प्रतिष्ठान छात्रों की परख करके तथा प्रशिक्षण के बाद इन छात्रों को अपने संस्थान में नौकरी दे सकेंगे।
  - इस प्रकार उद्योगों को कुशल और अनुभवी कर्मचारियों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  - उद्योगों को कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की लागत कम होगी, क्योंकि छात्रों को पहले से ही कुछ कौशल और अनुभव प्राप्त होगा।
  - एक छात्र-अभ्यर्थी पर प्रतिमाह 75% स्टाइपेंड की बचत होगी।
  - एक छात्र-अभ्यर्थी पर प्रतिमाह अधिकतम 9,000 रुपए तक की बचत होगी।
  - छात्र-अभ्यर्थी पर एपीएफ, बोनस एवं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होगा

नोट :

मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान
के कर-कमलों द्वारा

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना
ऑन जॉब ट्रेनिंग का शुभारंभ
मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान
के कर-कमलों द्वारा

नोट :

शहडोल में राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में 'मुख्यमंत्री स्कूटी योजना' लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

23 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 2022-23 में प्रथम स्थान पाने वाले 7 हज़ार 790 विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिये राशि प्रदान की और 'मुख्यमंत्री स्कूटी योजना' को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने प्रतीक स्वरूप शहडोल संभाग के छह विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबी सौंपी तथा 'मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना' के प्रशिक्षणार्थियों को ऑफर लेटर प्रदान किये।
- उल्लेखनीय है कि 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित करने के लिये 'मुख्यमंत्री स्कूटी योजना' की शुरुआत की गई है। इस योजना के ज़रिये इन विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिये सरकार इनके अकाउंट में राशि जारी करेगी। प्रदेश के 8 हज़ार छात्र-छात्राओं को हर साल इसका लाभ मिलेगा।
- इस योजना का लाभ पाने के लिये विद्यार्थियों को आवेदन देना होगा, जिसमें उन्हें इस बात का भी जिक्र करना होगा कि वे इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदना चाहते हैं या फिर पेट्रोल स्कूटी। इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिये सरकार 1 लाख 20 हज़ार रुपए देगी, जबकि सामान्य स्कूटी के लिये 90 हज़ार रुपए जारी किये जाएंगे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल में शीघ्र ही एयरपोर्ट निर्मित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में उद्योग स्थापना और निवेश को गति मिलेगी, जिससे रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।
- मुख्यमंत्री ने शहडोल को नगर निगम बनाने तथा यहाँ एक और महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा भी की।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रीड़ा परिसर विचारपुर में 6 करोड़ 43 लाख रुपए लागत से बनी एशिया की सबसे बड़ी आईएससी प्रमाणित स्पोर्टस क्लाइम्बिंग वॉल का वर्चुअल लोकार्पण भी किया।
- इसके साथ ही 96 करोड़ 62 लाख रूपए के कार्यों का भूमि-पूजन किया तथा 6.43 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण किया।
- मुख्यमंत्री ने युवा अन्नदूत योजना, एसएसजी क्रेडिट लिंकेज, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये।
- इस अवसर पर शहडोल ज़िले में विद्यालयीन स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही खेल सुविधाओं पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

नोट :

इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी देश में प्रथम

चर्चा में क्यों ?

23 अगस्त, 2023 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2023 में इंदौर ने देश में एक बार फिर सफलता का परचम फहराया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इसी श्रेणी में भोपाल ने 5वाँ, जबलपुर ने 13वाँ और ग्वालियर ने 41वाँ स्थान प्राप्त किया है।
- प्रमुख सचिव पर्यावरण गुलशन बामरा ने बताया कि 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रदेश के सागर को 188.02 अंकों के साथ देश में 10वाँ स्थान मिला है।
- 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास ने 180 अंकों के साथ देश में 6वाँ स्थान प्राप्त किया है।
- उल्लेखनीय है कि गत वर्ष देवास ने 200 में से 175.05 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया था। इंदौर को 200 में से 187, भोपाल को 181, जबलपुर को 172 और ग्वालियर को 114 अंक हासिल हुए हैं।
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम पाँच में से दो पुरस्कार मध्य प्रदेश के खाते में पांचवाँ हैं। इंदौर को पहला, आगरा को दूसरा, ठाणे को तीसरा, श्रीनगर को चौथा और भोपाल को 5वाँ स्थान मिला है।
- प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में 'प्राण' ऑनलाइन पोर्टल पर शहरों द्वारा भी स्व-मूल्यांकन किया जाता है।
- शहरों को ठोस अपशिष्ट, सड़क धूल, निर्माण और विध्वंस कचरे का प्रबंधन, वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण और औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में लागू की गई गतिविधियों और उपायों की रिपोर्ट देनी होती है।

श्री महाकाल लोक की तर्ज पर जामसांवली हनुमान मंदिर में होगा 'श्री हनुमान लोक'का निर्माण

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जामसांवली में श्री हनुमान लोक का विधि-विधान से भूमि पूजन कर यह घोषणा की कि श्री महाकाल लोक की तर्ज पर जामसांवली हनुमान मंदिर में 'श्री हनुमान लोक' का निर्माण किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में लगभग 26.50 एकड़ क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 'श्री हनुमान लोक'के निर्माण का कार्य आरंभ होगा।
- 'श्री हनुमान लोक'के निर्माण के प्रथम चरण में मराठवाड़ा वास्तु-कला से प्रेरित भव्य प्रवेश द्वार से भगवान के विराट स्वरूप की छवि दिखेगी। मुख्य प्रवेश द्वार से प्रथम प्रांगण तक 500 मीटर लंबा चिरंजीवी पथ बनेगा।
- पथ और प्रथम प्रांगण के 90 हज़ार वर्गफुट क्षेत्र में कलाकृतियों से अंजनी पुत्र हनुमान जी के बाल स्वरूप का मनोहारी चित्रण होगा। लगभग 62 हज़ार वर्गफुट क्षेत्र में मूर्तियों एवं कलाकृतियों के माध्यम से भक्त - शिरोमणि हनुमान जी के भक्ति स्वरूप का चित्रण होगा।
- रामलीला एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के लिये जलाशय के तट पर 12 हज़ार वर्गफुट क्षेत्र में मुक्ताकाशी मंच बनेगा, संजीवनी बूटी लाने वाले भगवान के संकटमोचक स्वरूप से प्रेरणा लेकर परिसर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनाया जाएगा।
- 'श्री हनुमान लोक'के समीप बहने वाली नदी तट के सौंदर्यीकरण एवं लैंडस्केपिंग के माध्यम से श्रद्धालुओं के बैठने आदि की व्यवस्था बनाई जाएगी।
- कम्युनिटी सेंटर, जन सुविधाएँ, ट्रस्ट ऑफिस, प्रशासनिक कार्यालय एवं कंट्रोल रूम आदि 37 हज़ार वर्गफुट में निर्मित किये जाएंगे। प्रसाद-पूजन सामग्री और भोजन आदि की व्यवस्था के लिये 120 दुकान एवं फूड कोर्ट बनेंगे।
- लगभग 400 चार पहिया एवं 400 दो पहिया वाहन क्षमता की डेढ़ लाख वर्गफुट क्षेत्र में पार्किंग विकसित की जाएगी।
- 'श्री हनुमान लोक'के निर्माण के द्वितीय चरण में रामटेकरी पर्वत की परिक्रमा के लिये संजीवनी पथ का विकास, अष्टसिद्धि केंद्र एवं संस्कृत विद्यालय, योगशाला प्रवचन हॉल एवं ओपन एयर थियेटर, जाम नदी पर घाट निर्माण, वाटर फ्रंट पाथ वे एवं सिटिंग एरिया, भक्त निवास, भोजनालय तथा गौ-शाला का निर्माण होगा।

मध्य प्रदेश में लगेंगी 1772 सूक्ष्म खाद्य उद्यम इकाइयाँ

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य उद्यम की 1772 इकाइयाँ लगने जा रही हैं। इन इकाइयों के लिये 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना'में ऋण स्वीकृत हो चुका है।

प्रमुख बिंदु

- सूक्ष्म खाद्य उद्यम की इन इकाइयों में सबसे ज्यादा 116 इकाइयाँ ग्वालियर में लगेंगी। दूसरे नंबर पर 100 इकाइयाँ खरगौन में, रीवा में 47, बालाघाट में 23, टीकमगढ़ में 27 और होशंगाबाद में 22 इकाइयाँ लगेंगी।
- उल्लेखनीय है कि योजना में उद्यमियों ने रुचि दिखाते हुए 10664 उद्यमियों ने ऋण के लिये आवेदन किया था। परीक्षण के बाद 1772 को ऋण देने योग्य पाया गया। बाकी आवेदनों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।
- विदित है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकार की भागीदारी के साथ सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिये वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार में सहायता देने के लिये 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना'शुरू की है।
- इसमें कौशल प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा मानकों एवं स्वच्छता के संबंध में तकनीकी जानकारी देने एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जा रहा है।
- इसके अंतर्गत इच्छुक लोगों को बैंक ऋण एवं डीपीआर तैयार करने के लिये मदद दी जाती है। पूंजी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता के लिये कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों को सहायता दी जा रही है।
- इसमें व्यक्तिगत रूप से स्थापित होने वाले उद्यम 35 प्रतिशत पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। लाभार्थी का योगदान 10 प्रतिशत होना चाहिये।
- स्व-सहायता समूहों को वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।

नोट :

- एक ज़िला-एक उत्पाद में चुने जाने वाले उत्पादों पर आधारित इकाइयों को प्राथमिकता मिलेगी।
- केंद्र सरकार ने सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्म खाद्य इकाइयों की सूची तैयार की है। इसमें मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के जमुना स्व-सहायता समूह की सफलता का उल्लेख है। इस समूह के सदस्यों को खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षण मिला।

मध्य प्रदेश में बनेगा रानी अवंती बाई कल्याण बोर्ड

चर्चा में क्यों ?

27 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के माता मंदिर क्षेत्र में अटल पथ के पास लोधी-लोधा-लोध क्षत्रिय महासभा के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोधी-लोधा-लोध समाज के कल्याण के लिये रानी अवंती बाई कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोधी समाज का स्वाधीनता आंदोलन और मध्य प्रदेश के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश में ऐच्छिक अवकाश के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रतिमा स्थापना की पहल भी की गई है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि लोधी-लोधा-लोध क्षत्रिय महासभा द्वारा दिये गए सुझाव पत्र पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आग्रह पर प्रदेश में मदिरा दुकानों के अहाते बंद करने का निर्णय लिया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने वित्त सेवा अधिकारी संघ की पुस्तक 'वित्त व्यवस्था' का किया विमोचन

चर्चा में क्यों ?

28 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में वित्त सेवा अधिकारी संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'वित्त व्यवस्था' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री को संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि 'वित्त व्यवस्था' पुस्तक में जुलाई 2023 तक के सामान्य प्रशासन, वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग आदि विभागों के नियम, निर्देशों का संकलन कर उनकी सरल भाषा में व्याख्या की गई है।
- पुस्तक प्रदेश के समस्त शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने में सहायक होगी।
- पुस्तक से वित्त विभाग के नियम निर्देशों को समझना भी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये सरल होगा। नियमों की सरल व्याख्या, राज्य के अधिकारियों के प्रतिदिन के कार्यों में उपयोगी साबित होगी तथा उनकी कार्य कुशलता और कार्यों में शुद्धता को बढ़ाएगी।

साँची सोलर सिटी कम करेगी लगभग 14000 टन कार्बन उत्सर्जन

चर्चा में क्यों ?

28 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश की पहली सोलर सिटी साँची में ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र, रूफटॉप, सोलर घरेलू उपकरण, सौर संचालित सार्वजनिक सुविधाओं के संयंत्रों और ई-मोबिलिटी से सालाना 13 हज़ार 747 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

प्रमुख बिंदु

- सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए प्रथम स्तूप से देश-विदेश में विख्यात भोपाल से 46 किलोमीटर दूर स्थित साँची शहर ने अब सौर ऊर्जा निर्माण में भी अपनी नई पहचान बनानी शुरू कर दी है।
- साँची में 8 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र स्थापित किये गए हैं। इनसे अनुमानित ऊर्जा उत्पादन 147.2 लाख यूनिट है। साल में इससे 6 करोड़ 3 लाख रुपए की बचत के साथ 12 हज़ार 656 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
- शहर के भवनों पर 235 किलोवाट के रूफटॉप सिस्टम स्थापित किये गए हैं, जिनसे 5 लाख यूनिट से अधिक ऊर्जा उत्पादन होगा और सालाना 22 लाख 65 हज़ार रुपए तथा 438 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी।
- घरेलू उपकरण- सोलर स्टडी लैंप, लालटेन, स्टेंड-लैंप से 11 टन, ऊर्जा दक्ष उपकरण, जैसे- एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और बीएलडीसी सीलिंग फैन से 452 टन, सार्वजनिक सुविधाओं के लिये स्थापित किये गए 54.45 किलोवाट के सौर संयंत्रों से 171 टन और ई-मोबिलिटी से 19 टन कार्बन की कमी होगी।
- यह कमी पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिये भी हितकर होगी। इन सबसे लगभग 160 लाख यूनिट ऊर्जा के साथ 7 करोड़ 18 लाख रुपए की बचत होगी।

प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को बीज संघ की सदस्यता

चर्चा में क्यों ?

29 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ की संचालक मंडल की बैठक में 8 प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को बीज संघ की सदस्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में बीज संघ की वार्षिक साधारण सभा 12 सितंबर को आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

नोट :

- केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देशन में मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट-2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर गठित भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता से अवगत कराते हुए प्रबंध संचालक ए.के. सिंह ने बताया कि बीज संघ के अतिरिक्त 282 प्राथमिक बीज समितियों और 32 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा संघ की सदस्यता ग्रहण की जा चुकी है।
- संचालक मंडल की बैठक में वार्षिक साधारण सभा में रखे जाने वाले अनिवार्य विषयों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- मध्य प्रदेश में निर्मित बीज संघ के गोदाम-सह-ग्रेडिंग प्लांट में सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर वायर फेंसिंग कराए जाने का भी निर्णय लिया गया।

नवाचारी ई-शासन-प्रशासन व्यवस्थाएँ स्थापित करने में आगे बढ़ा मध्य प्रदेश, 23 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिले

चर्चा में क्यों ?

30 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारी उपयोग से ई-गवर्नेंस व्यवस्थाओं को लागू कर मध्य प्रदेश ने वर्ष 2007 से लेकर अब तक राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के लिये 23 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार जीते हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नवाचारी आईटी-आधारित गवर्नेंस व्यवस्थाओं को मिले प्रोत्साहन से प्रेरित होकर कई विभागों ने नवाचारी व्यवस्थाएँ लागू की हैं, जिनसे विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के लक्षित हितग्राहियों को लाभ हुआ है।
- इनमें से कई प्रयासों को अन्य राज्यों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में भी लागू करने योग्य मानते हुए उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता के लिये प्रशंसा मिली है।
- वर्ष 2007 में एकीकृत कोषालय कंप्यूटरीकरण, 2008 में जबलपुर कलेक्ट्रेट में टेली-भुगतान, 2010 में वनवासियों के सर्वेक्षण की व्यवस्था और एमपी ऑनलाइन, समग्र पोर्टल, पंच परमेश्वर पोर्टल, इंदौर 311 ऐप, पेंशन पोर्टल, ऑनलाइन सामाजिक सुरक्षा योजना प्रबंधन प्रणाली, एमपी श्रम सेवा पोर्टल, स्पर्श-दिव्यांगों की सहायता, पुनर्वास और दिव्यांगों को सशक्त बनाने की विशेष परियोजना, राज्य स्कूल शिक्षा पोर्टल, स्वचालित मीटरिंग सिस्टम और फायर अलर्ट एवं संदेश देने जैसी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है।

नोट :

- हाल ही में, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जल- (सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एक्जीबिशन) परियोजना के लिये सिल्वर पुरस्कार जीता।
  - इसका उद्देश्य जल उपचार संयंत्रों, पंप हाउसों और स्टोरेज की मॉनिटरिंग, नियंत्रण और डाटा प्रबंधन की सही समय पर जानकारी देने की व्यवस्था बनाना है, जिससे पानी की आपूर्ति तय मापदंडों और प्रभावी ऊर्जा प्रबंधन के साथ हो सके। असामान्य स्थितियों पर ऑपरेटर्स को सतर्क करने की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि खतरों की संभावना को कम किया जा सके।
- वर्ष 2021 में इंदौर-311 एप्लीकेशन जैसी पहल को देश भर में तारीफ मिली। इस एप्लीकेशन ने स्वच्छता में इंदौर को नंबर वन बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - इंदौर-311 ऐप पर अपनी समस्याओं को उठाने और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के लिये प्रेरित करने का सबसे आसान तरीका है। इंदौर-311 इंदौर के नागरिकों के लिये अपनी आवाज़ उठाने का मंच है।
  - सिविल विभागों को समस्याओं की रिपोर्ट करने, विश्लेषण करने, प्रबंधन करने और समस्याओं को हल करने में इस पहल ने इंदौर को और ज़्यादा बेहतर शहर बनाने में मदद की है।
- वर्ष 2018 में, पंच परमेश्वर पोर्टल को गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तकनीक का उपयोग कर ई-गवर्नेंस में रचनात्मक तरीकों से खेलों की उत्कृष्टता के लिये खेल और युवा कल्याण निदेशालय द्वारा सिल्वर पुरस्कार प्राप्त किया गया।
- भोपाल के गोद लेने संबंधी जानकारी की स्रोत एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के रचनात्मक हस्तक्षेप को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है।
- अनमोल देश की पहली राज्यस्तरीय ई-पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विशेषज्ञ एडॉप्शन एजेंसी (एसएए) में रह रहे बच्चों की मॉनिटरिंग करना है। अनमोल एक एकल सूचना केंद्र है, जो बच्चों की स्थिति, उन्हें अपनाने की प्रक्रिया, माता-पिता को अपनी प्रतीक्षा सूची की स्थिति की जानकारी देता है, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्धता की जानकारी देता है और लिंग के आधार पर बच्चों की स्थिति पर निगरानी रखता है।
- स्कूल शिक्षा पोर्टल एक समग्र पोर्टल है, जो एक एकीकृत ई-गवर्नेंस व्यवस्था के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो स्कूल शिक्षा क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करेगा। प्रक्रियात्मक, पारदर्शी और जवाबदेह गवर्नेंस देने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने में मददगार साबित हुआ है।
- लोगों को प्रभावी ई-प्रशासन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ देने और आईटी के नवाचारी उपयोग को आगे बढ़ाने के लिये अन्य प्रयासों में मुख्य रूप से ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी की योजना हेतु जियोमेटिक्स आधारित एकीकृत सूचना तंत्र एप्लीकेशन, नागरिक सुविधा और शिकायतों के लिये टेली-समाधान कॉल सेंटर, जन मित्र समाधान केंद्र, ग्वालियर, ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, एसएमएस आधारित ट्रांसफार्मर जानकारी और प्रबंधन सिस्टम शामिल हैं।

नोट :